



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / काइल संख्या / Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	V2/4/EA2/GDM/2016	09/AC/2016	30.03.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-057-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	30.10.2017	जारी करने की तारीख / Date of issue:	31.10.2017
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अथ आयुक्त/ सयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गान्धीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-
M/s. Sanghi Industries Ltd., Cement Division (Clinker Unit), Sanghipurem, Taluka- Abdasa, Kutch,

इस आदेश(अपील) से व्यभिक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- (A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत विमर्शित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-
- (i) वगीकरण मुद्दों/कांसे से सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जाती चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.
- (ii) उपरोक्त पैराग्राफ 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की परिचय श्रेणी पीठिका, , द्वितीय तल, बहमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जाती चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhamali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above
- (iii) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये फॉर्म EA-3 को धारा 5(1) में दूजे किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि, ब्याज की राशि और लगाना गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयंसेवक आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

- (B) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-5 में धार प्रतियों में की जा सकती एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रामाणिक होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि, ब्याज की राशि और लगाना गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयंसेवक आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) कित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित परपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (जसमें से एक प्रति प्रस्तापित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उप-आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपील की न्यायाधिकारण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकारण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपील न्यायाधिकारण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि इस कथोड़ रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है।
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवैट जमा की गयी गलत राशि
(iii) सेनवैट जमा निवन्तावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के अंश से पूर्व किसी अपील न्यायाधिकारण के तहत विचारणीय स्थिति अर्थात् अपील को लागू नहीं होने।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम पारंतुक के अंतर्गत अत्र राशि, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, कित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौकी मजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अंतर गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंतर गृह से दूसरे अंतर गृह पारगमन के दौरान, या किसी अंतर गृह में या अंतर गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंतर गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबैट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई लागू अथवा समावधि पर का बट में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संघेषण के 3 महीने के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अद्यतनी के साथ-साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Chalan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदावती की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। /
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की सिखा नहीं कार्य हो करने के लिए यथास्थिति अपील न्यायाधिकारण को एक अपील या केटीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if existing Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकारण (सर्वे विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपील न्यायाधिकारण को अपील दर्जित करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपील न्यायाधिकारण वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

:: ORDER IN APPEAL ::

38

The Commissioner, Central Excise & Service Tax, Kutch (hereinafter referred to as "appellant") has filed the present appeal against Order-in-Original No. 9/Asstt. Commr./2016 dated 30.03.2016 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Central Excise Division, Bhuj (hereinafter referred to as "lower adjudicating authority") in the case of M/s. Sanghi Industries Limited (Grinding Unit), P.O. Sanghipuram, Motiber, Tal. Abdasa, Dist.Kutch (hereinafter referred to as "respondent").

2. Briefly stated, facts of the case are that, audit revealed that the respondent has wrongly availed cenvat credit of Rs. 53,314/- during the period July, 2016 to February, 2007 on M.S. Pipes/G.I. Pipes falling under Chapter 73 of the first schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 in credit account of capital goods. SCN No. IV/21-16/LAR-1817/07 dated 08.07.2009 was issued to the respondent for recovery of wrongly availed cenvat credit of Rs. 53,314/- along with interest under Rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as "CCR, 2004") read with Section 11A/11A of Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as "Act") and to impose penalty under Rule 15 of CCR, 2004 read with Section 11AC of the Act. The lower adjudicating authority vide impugned order dropped the proceedings initiated vide SCN dated 08.07.2009 on the ground that SCN did not incorporate specific allegations enumerating existence of ingredients mentioned in proviso to Section 11A (1) of the Act.

3 Being aggrieved by the impugned order, department preferred the present appeal, *inter alia*, on the grounds that decisions in the case of Shree Ram Steel Rolling Mills reported as 2008 (221) ELT 333 (Bom.), Hindustan Coco Cola Beverages Pvt. Ltd. reported as 2010 (259) ELT 134 (Tri.) and Raymond Ltd. reported as 2008 (230) ELT 381 (Tri.) and relied upon by the lower adjudicating authority are not relevant in the facts and circumstances of the present case; that judgment in the case of Pradyumna Steel Ltd. reported as 1996 (82) ELT 441 (SC) is squarely applicable in the present case; that if the audit was not conducted, the fact of wrong availment of cenvat credit by the respondent would not have been known to the department, hence, it is clearly evident that the respondent suppressed the fact of wrong availment of cenvat credit; that the respondent had willfully avoided to provide complete details of cenvat credit availment; that the respondent had suppressed the availment of cenvat credit on M.S. Pipes/G.I. Pipes from the department and hence the extended period of limitation was rightly invoked in the SCN.

4. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Ishan Bhatt, Advocate, who submitted that grounds of appeal are not correct; that no suppression of facts was ever alleged in SCN; that SCN does not say anywhere what had not been submitted by the respondent; that they were required to file ER-1 Returns and they have filed ER-1 Returns; that they were not required to file details of invoices on which credit is taken; that department never asked any information before audit and whatever information was asked for during audit was all submitted; that SCN is based on audit objection only; that suppression of facts cannot be alleged now as it has not been alleged in SCN; that they would submit written P.H. submissions within 2 weeks. No one appeared from the department despite P.H. notices issued to them.

4.1 The respondent, in their written submission stated that even if the submission of the department in their appeal regarding invocation of extended period of limitation is accepted, there can be no denial of cenvat credit in the present case as the goods in question are specifically covered by the definition of capital goods under Rule 2(a)(A) of CCR, 2004 during the relevant period. Clause (vi) of Rule 2(a)(A) specifically includes "tubes and pipes and fittings thereof" under the definition of capital goods. The SCN dated 08.07.2009 does not dispute the fact that the pipes were used within the factory of the respondent. The only allegation in the SCN is that the respondent has availed cenvat credit on 'unspecified' capital goods. However, the allegation of SCN is completely incorrect inasmuch as pipes were specifically covered in the definition of capital goods during the material time.

4.2 The lower adjudicating authority has rightly dropped demand on the ground that entire demand is beyond normal period of limitation and the SCN does not incorporate any specific allegation enumerating the existence of ingredients mentioned in proviso to Section 11A(1) of the Act.

4.3 The department has relied upon case law of the Hon'ble Supreme Court in the case of Pradyumna Steel Ltd. – 1996 (82) ELT 441 (SC) where the Hon'ble Supreme Court has held that "*Mere mention of wrong provision of law when power exercised is available though under a different provision is by itself not sufficient to invalidate the exercise of that power.*". The reliance placed on the said judgment is completely misplaced. In the present SCN, it is not a case of quoting wrong provision of law but a case of not alleging ingredients which are required to be established to invoke extended period of limitation. This distinction was clearly explained by the Hon'ble High Court of Madras in the case of Super Spinning Mills Ltd. – 2015 (324) ELT 552 (Mad.).

4.4 The SCN is the foundation of the demand. Allegations which are not present in the SCN cannot be urged against the assessee at a later stage. The appellant relied

on the decisions in the case of Ballarpur Industries Ltd. – 2007 (215) ELT 489 (SC) and Reliance Ports & Terminals Ltd. – 2016 (334) ELT 630 (Guj.) in support of their contention.

FINDINGS: -

5. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order, appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the appellant. The issue to be decided is whether in the facts and circumstances of the present case, the impugned order passed by the lower adjudicating authority dropping proceedings initiated vide SCN dated 08.07.2009 is correct or not.

6. I find that the lower adjudicating authority has clearly held that the SCN did not incorporate specific allegations enumerating existence of ingredients mentioned in proviso to Section 11A (1) of the Act. The department relied on judgment in the case of Pradyumna Steel Ltd. reported as 1996 (82) ELT 441 (SC) and contended that extended period of limitation was rightly invoked in the SCN. The respondent contended that it is not a case of quoting wrong provision of law but a case of not alleging ingredients which are required to be established to invoke extended period of limitation, hence the said decision is not applicable to the present case. I find force in the arguments made by the respondent. I find that period of availment of disputed cenvat credit is July, 2006 to February, 2007 for which demand notice was issued on 08.07.2009. I find that in catena of decisions, it has been held that the extended period of 5 years as provided under proviso to Section 11A(1) of the Act is not available to the Department without bringing out details of suppression of facts or willful mis-statement or misdeclaration with intent to evade payment of Central Excise duty. I further find that in the case of Pradyumna Steel Ltd. reported as 1996 (82) ELT 441 (SC), the facts before the Hon'ble Supreme Court was that wrong provision was mentioned/quoted in the SCN, however in the present case the SCN did not indicate ingredients of suppression of facts or willful mis-statement or misdeclaration with intent to evade payment of Central Excise duty. Hence, it is not a case of wrong quoting of provisions and therefore, ratio of the said judgment relied upon by the department is not relevant at all to the facts and circumstances of present case. Hence, I find that department has not alleged suppression of facts etc. but demanded duty of extended period and therefore the SCN suffers from legal infirmity and the lower adjudicating authority has correctly dropped the demand.

7. I find that the respondent has contended that M.S. Pipes/G.I. Pipes are specifically covered by clause (vi) of Rule 2(a)(A) under the definition of capital goods. I would like to reproduce the relevant part of definition of capital goods as provided under Rule 2(a) of CCR, 2004, prevailing at the material time, which reads as under:

Rule 2(a) "capital goods" means –

(A) the following goods, namely: -

(i) all goods falling under Chapter 82, Chapter 84, Chapter 85, Chapter 90 of the First Schedule to the Excise Tariff Act;

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) Tubes and pipes and fittings thereof, and

(vii)

(Emphasis supplied)

8. In view of the above wordings, I find that tubes and pipes and fittings thereof are capital goods as per Rule 2(a)(A)(vi) of CCR, 2004 and hence cenvat credit availed on M.S. Pipes/G.I. Pipes cannot be denied to the respondent.

9. In view of above legal and factual position, I uphold the impugned order and reject the appeal filed by the department.

९.१. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9.1. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.

(कुमार संतोष)

आयुक्त (अपील्स)

By Regd. Post AD

To,

M/s. Sanghi Industries Limited (Grinding Unit),
Sanghipuram,
Motiber, Tal. Abdasa,
Dist.Kutch

मे. सांघी इंडस्ट्रीज लीमिटेड,
संघीपुरम,
मोटिबर, तालुका - अबडासा,
डिस्ट्रिक्ट - कच्छ

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise Commissionerate, Gandhidham.
- 3) The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division, Bhuj – Kutch.
- 4) Guard File.